बदहाल व्यवस्था की भेंट चढ़े बिहार के बच्चे

बिहार में सरकारी निष्क्रियता की वजह से आसानी से काबू की जा सकने वाली एक बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया। इस बीमारी से अब तक 173 बच्चों की जान चली गई है। बता रहे हैं सत्यव्रत मिश्रा

बीते 10 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराकर पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे थे। सभी जनता दल (यू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच नए विवाद को लेकर ज्यादा उत्सुक थे। अचानकर एक सवाल मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) या 'चमकी बुखार' का उठा और नीतीश के चेहरे के भाव बदल गए। उनका जवाब था, 'यह बीमारी आम तौर पर बरसात के पहले फैलती है। विभाग ने इस बारे में कदम उठाए हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने इस बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया है। हमारी यह गुजारिश है कि लोग अपने बच्चों को रात में भरपेट खाना खिलाकर ही सोने दें। इस बार अब तक मामले लगातार आ रहे हैं। लगता है कि अभियान में सुस्ती आई है।'

उन्होंने तुरंत इस मसले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से सफाई मांगी। अधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के अस्पतालों में पूरा इंतजाम किया गया है। प्रधान सचिव ने बताया, 'अब तक हाईपोग्रलाईसिमिया (खून में शक्कर की कमी) से अब तक 10 बच्चों की मौत हुई है। हमने पूरे इंतजाम किए हैं। उम्मीद है कि मॉनसून की आमद के बाद इस बीमारी पर लगाम लग जाएगी।' सरकारी दावे की हकीकत एक हफ्ते के भीतर लोगों के सामने थी।

इस दावे के पांच दिन के भीतर मुजफ्फरपुर जिले में 70 बच्चों की मौत हो चुकी थी। शहर के दो सबसे बड़े अस्पतालों, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) और केजरीवाल अस्पताल, में नए रोगियों की बाढ़ आ चुकी थी। जिले में कुल मिलाकर 280 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे और पूरा उत्तर बिहार भय के साये में था।

नौ बिस्तरों वाले आईसीयू और 20 बिस्तर वाले बाल वार्ड का एसकेएमसीएच इतनी बड़ी तादाद में रोगियों के लिए तैयार नहीं था। नतीजा पूरी व्यवस्था चरमरा गई और एक के बाद एक कई बच्चे काल के गाल में समाते चले गए।

हालात काबू से बाहर होता देख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पिछले से पिछले रविवार को अस्पताल के दौरे पर आए। साथ में थे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय। वैसे तो चौबे को 12 जून को इस बीमारी को लेकर समीक्षा बैठक करनी थी, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया क्योंकि उस दिन चौबे को भागलपुर में 'विजय जुलूस' में शिरकत करनी थी। हालांकि, इस दौरे के दौरान चौबे ऊंघते नजर आए, जबकि मंगल पांडेय को बच्चों से ज्यादा क्रिकेट स्कोर की चिंता थी। खुद हर्षवर्धन अपने पांच साल पुराने वादों को ही दोहराते नजर आए।

आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के एक दिन पहले सोमवार शाम को सरकार हरकत में आई। अस्पताल में तीन नए आईसीयू के निर्माण की अनुमति दी गई। साथ ही, सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चालू हालत में लाने को कहा गया। पटना और दरभंगा से 10 डॉक्टरों की टीम मुजफ्फरपुर भेजी गई। राज्य सरकार ने चमकी बुखार के रोगियों के लिए मुफ्त एंबुलेंस सेवा और मुफ्त इलाज का भी ऐलान किया। तब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी थी।

मंगलवार को नीतीश जब अस्पताल आए, तो मरीजों के परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पूरा अस्पताल 'नीतीश वापस जाओ' के नारों से गूंज रहा था। उसके कुछ घंटे बाद ही मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पहली बार स्वीकार किया कि राज्य सरकार अब तक इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानती है।

• • •

मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में दरियापुर मुसहरी में 50-60 महादलित घर हैं। इस बस्ती में बीते 10 दिनों में दो बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। फूस के एक घर के बाहर बैठे नूनू महतो बताते हैं, 'मेरे प्रिंस को भोज में जाना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन पड़ोस के गांव में एक मुंडन संस्कार था। हम सभी गए थे, दिन में खाना खाकर शाम को वापस आ गए। वापसी में उसने अपनी बहिनों के साथ समोसा भी खाया था। शाम को थककर सो गया था और सुबह में चमकी आने लगी। हम उसे तुरंत केजरीवाल अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई।'

> **चमकी बुखार की जड़ में है, कुपोषण, गर्मी और उमस। इस बीमारी में रातोरात रक्त और ग्लूकोज की मात्रा निम्न स्तर पर पहुंच जाती है**

करीब चार वर्ष के प्रिंस की 14 जून को मौत हुई थी। उसकी मां शीला देवी के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनका कहना है, 'वह मेरी आंखों का तारा था। अब मैं कैसे जीऊंगी?' उनकी बेटियां अपनी मां के पास चुपचाप बैठी थीं। उनकी रसोई भी खाली थी, मिट्टी के चूल्हे पर जैसे कई दिनों से कुछ नहीं बना हो।

कुछ ऐसी ही हालत पड़ोस के सुबोध पासवान और रेखा देवी की थी। उनकी छह वर्षीय बेटी निधि भी 13 जून को काल के गाल में समा चुकी थी। बमुश्किल अपने आंसुओं को रोकती हुई रेखा बताती हैं, 'वह हर दिन की तरह जल्दी ही उठी थी। मेरे साथ गांव की दुकान से दाल लाने भी गई थी। वहां से वापस आने पर उसका बदन अकड़ने लगा। उसके पापा उसे तुरंत मोटरसाइकिल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया। उसी शाम मेरी बेटी गुजर गई।'

इस बीमारी ने पड़ोस के रामपुर साह मुसहरी में भी दो चचेरे भाइयों की जान ले ली। दो वर्ष के राजकुमार की मां चिंता देवी ने बताया, 'हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, नहीं तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। जब राजू बुखार से तड़पने लगा, तो हमारी समझ में ही कुछ नहीं आया। हम उसे पड़ोस में एक हकीम के पास ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।'

इसके अगले ही दिन चिंता के देवर सुनील मांझी के 19 महीने के बेटे प्रिंस की तबीयत भी खराब हो गई और कुछ ही घंटे में वह भी काल के गाल में समा गया। मांझी ने कहा, 'क्या कहूं? उसने शाम को दूध पिया, लेकिन सोना नहीं चाहता था। मेरे साथ खेलना चाहता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। वह फिर कभी उठा ही नहीं।'

कुछ ऐसी ही कहानी प्रांत के 170 से ज्यादा परिवार की भी है, जिन्होंने सरकारी निष्क्रियता की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है।

• • •

ज्यादातर मामलों में बच्चों की मौत एईएस की वजह से हाईपोग्लाइसिमिया या रक्त में ग्लूकोज की अत्यधिक कमी से हुई है। राज्य सरकार अब भी चमकी बुखार के नाम से प्रचलित इस बीमारी के कारण के बारे में नहीं जानती है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में दिमाग की झिल्ली सूज जाती है, जिस वजह से तेज बुखार, तेज सिरदर्द, उल्टी, कंपकंपी और अकड़न होती है और लकवा तक मार जाता है।

राज्य सरकार इस बीमारी का पूरा ठीकरा लीची और गर्मी के सिर पर फोड़ रही है। हालांकि, सरकारी अधिकारी इस बारे में ज्यादा जानते भी नहीं हैं। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा, 'इस बारे में कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम भरोसे से कुछ कह नहीं सकते।'

डॉक्टरों और विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। टीएचएसटीआई, फरीदाबाद की कार्यकारी निदेशक और रॉयल सोसाइटी में पहली भारतीय महिला फेलो गगनदीप कंग ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'यह बीमारी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के कारण हो सकती है। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए अच्छे प्रयोगशालाओं और कुशल पेशेवर वैज्ञानिकों की जरूरत है। इस बारे में राज्य सरकार को एक विस्तृत अध्ययन भी करवाना चाहिए।'

हालांकि, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के सदस्य और बाल रोग विशेषज्ञ अरुण शाह के मुताबिक गर्मी, गंदगी और कुपोषण इस बीमारी के लिए मुख्य रूप से दोषी है। शाह मुजफ्फरपुर में रहते हैं और बीते 20 वर्षों से एईएस मामलों पर नजर रखे हुए हैं। वह मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ जैकब जॉन की टीम में भी शामिल थे, जिन्होंने एईएस पर विस्तृत शोध किया था। इस टीम ने इस बीमारी के लिए एक मानक प्रक्रिया बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

उन्होंने कहा, 'सरकार पूरा ठीकरा लीची पर फोड़ रही है, जो सही नहीं है। हमने अपने शोध में पाया था कि कच्ची या सड़ी लीची में एमसीपीजी नाम का एक विष जरूर होता है। ये बीमारी का एक कारण हो सकता है, लेकिन इकलौता कारण नहीं। इस बीमारी की जड़ में है कुपोषण, गर्मी और उमस। दरअसल, इस बीमारी में रातोरात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। स्वस्थ बच्चों के शरीर मे तो ग्लूकोज का अतिरिक्त भंडार होता है, लेकिन कुपोषित बच्चों में नहीं। इसीलिए इस बीमारी का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों के बच्चों पर होता है।'

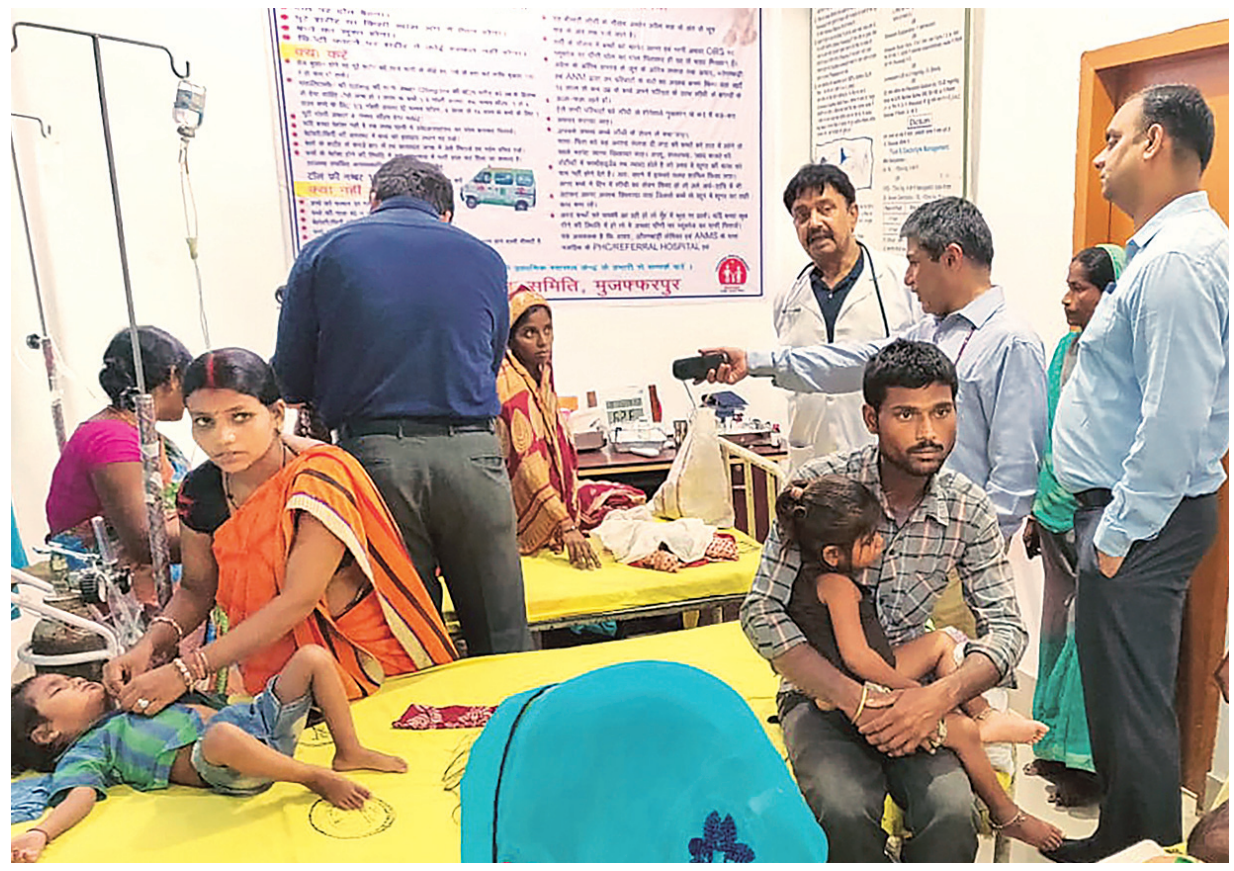

• • •

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माहौल काफी गमजदा है। हर ओर बीमार बच्चे, गरीब माता-पिता और काम के बोझ तले दबे डॉक्टर ही दिखाई देते हैं। मरीजों की देखभाल में जुटे एक डॉक्टर ने बताया, 'यहां हम पर काफी दबाव में हैं।'

लगातार फोन पर मंत्रियों, अधिकारियों और पत्रकारों के सवालों से घिरे एसकेएमसीएच के अधीक्षक सुनील कुमार शाही अपना गुस्सा चाहकर छुपा नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा, 'इस वक्त हमारा अस्पताल अपनी क्षमता से ज्यादा पर काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर चौबीसों घंटे काम पर हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें अपना काम करने दीजिए।'

अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक इस वक्त एसकेएमसीएच में करीब 100 बच्चे एईएस का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे बाल रोग विभाग में कुल मिलाकर 21 डॉक्टर हैं। राज्य सरकार 10 डॉक्टरों को और भेज रही है। हालांकि, असल समस्या नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ को लेकर है। हमें कम से कम हर दो मरीज पर एक नर्स की जरूरत है।' विभाग के पास इस वक्त महज आधी दर्जन नर्स हैं।

डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। उन्होंने कहा, 'इस वक्त अस्पताल के निजी सुरक्षाकर्मियों के भरोसे काम चला रहा है। इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद लोगों ने अब तक यहां हमारे साथ कोई बेअदबी नहीं की है। हालांकि, जहां बच्चों की मौत हो रही हो, वहां स्थिति किसी भी क्षण खराब हो सकती है।'

बाल वार्ड में स्थिति काफी खराब है। वार्ड पूरी तरह से लोगों से अटा पड़ा है। बच्चे दर्द और गर्मी के मारे चिल्ला रहे हैं। वार्ड में एक डॉक्टर ने बताया, 'यहां बीते साल एसी लगने वाला था। इसीलिए सभी खिड़कियां बंद की गई। हालांकि, पैसे की किल्लत की वजह से एसी नहीं लग पाया। इसीलिए अब इस वार्ड में हवा निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं बची है।'

लोग भी डॉक्टरों के काम की तारीफ कर रहे हैं। सात वर्षीय हरिकिशन के पिता रवि राय ने बताया, 'अस्पताल में कई समस्याएं हैं, लेकिन डॉक्टरों ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने मेरे बेटे का अच्छे से इलाज किया है। उम्मीद है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा।'

सीतामढ़ी जिले के जमालउद्दीन अंसारी का भांजा आलम आईसीयू में भर्ती है। उन्होंने बताया, 'डॉक्टर अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अगर कोई दोषी है, तो यह पूरी व्यवस्था और सरकार है। नेताओं को हमारे बच्चों से ज्यादा चिंता हमारे वोट की रहती है।'

• • •

मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था को भी सबके सामने ला दिया। एसकेएमसीएच के एक डॉक्टर ने बताया, 'इस बीमारी को बेहद आसानी से रोका जा सकता था। जरूरत थी जागरूकता और बेहतर प्राथमिक अस्पतालों की। इन अस्पतालों ने अपना काम नहीं किया और इसी वजह से पूरी व्यवस्था ही चौपट हो गई।'

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में 1,719 गांव हैं, जिनमें से महज 630 में स्वास्थ्य केंद्र हैं। जिले के सभी 103 प्राथमिक अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शून्य रेटिंग मिली है। वहीं, इनमें से 98 को तो मंत्रालय ने जांच के लायक भी नहीं पाया था क्योंकि खुद राज्य सरकार के मुताबिक उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा, 'कुछ दिक्कतें हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि बारिश के बाद इस बीमारी से राहत मिलेगी।' शनिवार को बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे भी दी, लेकिन सरकारी निष्क्रियता पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में सभी 103 प्राथमिक अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय से शून्य रेटिंग मिली है फोटो:पीटीआई

निवेशकों को भा रहे अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप

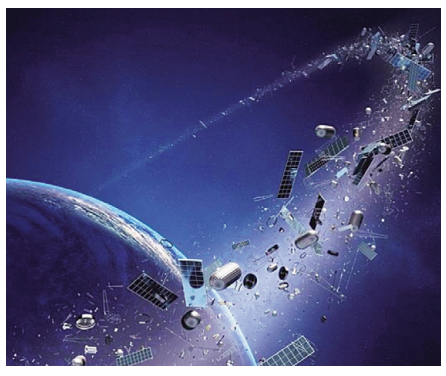

रॉयटर्स

हथेली के आकार के उपग्रह से लेकर स्वच्छ ईंधन युक्त उपग्रह बनाने के क्षेत्र में आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक युक्त भारतीय स्टार्टअप तेजी से पैर पसार रही हैं और निवेशक भी इस दौड़ में अपनी राह बनाते दिख रहे हैं। विषाक्तता रहित और इलेक्ट्रिक रसायनों वाले थ्रस्टर्स की सहायता से उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना पर काम कर रही बेंगलूरु स्थित बैलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने हाल ही में निवेशकों के एक समूह से 30 लाख डॉलर की वित्त उगाही की है। कंपनी के सह संस्थापक यशस कर्णम ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। वेंचर कैपिटल फंड आईडीएफसी परंपरा की अगुआई में बैलाट्रिक्स की प्री सीरीज-ए वित्त उगाही का दौर चला। अन्य 7 निवेशकों में अरबपति परिवार से संबंध रखने वाले सुमन कांत मुंजाल तथा बॉलीवुड हस्ती दीपिका पदुकोणे शामिल रहे।

पृथ्वी निगरानी संबंधी उपग्रहों का निर्माण और परिचालन करने वाली मुंबई स्थित कावा स्पेस कंपनी ने सीड राउंड की वित्त उगाही की है। हालांकि कंपनी ने कुल राशि का खुलासा नहीं किया है। बैलाट्रिक्स और कावा उन दर्जनों भारतीय स्टार्टअप में से एक हैं जो उपग्रह, रॉकेट और अंतरिक्ष अभियानों में मददगार दूसरी सहायक सामग्रियों का निर्माण कर रहे हैं।

इन स्टार्टअप द्वारा की जा रही वित्त उगाही अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बड़ी छलांग लगाने की ओर इशारा करती है। अंतरिक्ष उत्पादों को ऑनलाइन बेचने वाले मार्केटप्लेस सैटसर्च के सह-संस्थापक नारायण प्रसाद बैलाट्रिक्स की वित्त उगाही के संदर्भ में कहते हैं, 'इससे पहले भारत में तकनीक के क्षेत्र में निवेश करने वाली किसी वीसी फर्म ने अंतरिक्ष क्षेत्र में इतना अधिक निवेश नहीं किया।'

स्टार्टअप डेटा पर नजर रखने वाली फर्म ट्रैक्सन और निवेशकों के साक्षात्कार के आधार पर बैलाट्रिक्स और कावा के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र की 7 अन्य भारतीय कंपनियों ने भी वित्त उगाही की है। पृथ्वी से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट में बढ़ती गतिविधियों से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की रूचि बढ़ रही है। आज के समय फसल निगरानी से लेकर रक्षा, शहरी प्लानिंग, लागत कम करने और चित्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छोटे और सस्ते उपग्रहों का चलन तेजी से बढ़ा है।

सकारात्मक समय

पिछले 5 सालों में करीब 2 दर्जन भारतीय स्टार्टअप यूनीकॉर्न श्रेणी (एक अरब डॉलर से अधिक का मूल्यांकन) में शामिल हुए हैं। इनमें से अधिकांश मध्यम वर्गीय श्रेणी के ग्राहकों और घरों पर केंद्रित हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र की भारतीय तकनीकी कंपनियों में नए स्टार्टअप और निवेशक आ रहे हैं जो अंतरिक्ष में खोजबीन से लेकर दूसरे अभियानों में अपनी रूचि दिखा रहे हैं। बेलाट्रिक्स में निवेशक जतिन देसाई बताते हैं कि आने वाले वर्षों में उपग्रह प्रक्षेपण को लेकर इन कंपनियों में निवेशकों की रूचि वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। वह कहते हैं, 'इससे हमे संभावनाओं से भरा एक बड़ा बाजार मिलेगा।'

सलाहकार फर्म फ्रॉस्ट एंड सुलिवन का अनुमान है कि साल 2018 से 2020 के अंदर करीब 17,000 छोटे उपग्रह प्रक्षेपित होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र के 3 भारतीय स्टार्टअप में निवेश करने वाले राजाराम कहते हैं, 'यहां काफी पैसा कमाया जा सकता है..... यह उद्यमियों के लिए उत्साहजनक समय है।'

चुनौती बरकरार

हालांकि अभी भी बहुत से निवेशक अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप के लिए अपने द्वार नहीं खोल रहे हैं। मेपल कैपिटल, आइडिया स्प्रिंग कैपिटल, भारत इनोवेशन फंड और 3वन4 कैपिटल आदि कई भारतीय वेंचर कैपिटल फर्मों का कहना है कि उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के बहुत से स्टार्टअप से बातचीत की है लेकिन फिलहाल वे इंतजार करने की नीति अपना रही है। आइडिया स्प्रिंग के मैनेजिंग पार्टनर एन दोरस्वामी अंतरिक्ष क्षेत्र की परियोजनाओं में निर्माण, परीक्षण, सरकारी अनुमति आदि के बारे में बताते हुए कहते हैं, 'रिटर्न के हिसाब से इन योजनाओं की परिपक्व अवधि काफी अधिक है।'

ब्रिटेन ने की ईरान तनाव पर चर्चा

ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में पश्चिम एशिया के लिए मंत्री एंड्र्यू मॉरिसन रविवार को तेहरान पहुंचे और लगातार बढ़ रहे क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के शीर्ष राजनयिकों से मिले। मॉरिसन ने ईरानी विदेश मंत्रालय में विदेशी संबंधों की रणनीति परिषद के प्रमुख कमाल करजई से द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों और परमाणु समझौते पर चर्चा की। *भाषा*

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम)
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
सी-3, मथुरा रोड, ओपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076
कॉनकॉर CONCOR

निविदा आमंत्रण (आईएफबी)

निविदा सं. CON/T/DCONT-11, 60020FT/EO&SA/2019

निविदा दस्तावेज के सेक्टर-V में दिए तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार स्टील ड्राई फ्रेट कंटेनरों के 11,600 नग (1600 नग टाईप-I + 1500 नग टाईप-II + 8500 नग टाईप-III) की आपूर्ति हेतु प्रख्यात और स्थापित निर्माताओं से 'दो पैकेट' निविदाकरण पद्धति में ऑनलाइन खुली/वैश्विक ई-निविदा आमंत्रित हैं। निविदाकारों को किसी एक या दो या सभी तीन टाईप के कंटेनरों के लिए कोटेशन की अनुमति है।

अनुमानित लागत	₹306.5 करोड़
निविदा दस्तावेज का मूल्य	₹1000.00 या यूएस$ 15.00 जीएसटी सहित ऑनलाइन भुगतान गेटवे माध्यम से कॉनकॉर को
निविदा प्रतिभूति (धरोहर राशि)	₹20,00,000/- (भारतीय रुपये) या यूएस$ 28,970
ई-निविदा डाउनलोड अवधि (निविदा बिक्री की अविध)	24.06.2019 समय 11:00 बजे से 02.08.2019 समय 17:00 बजे तक
बोली पूर्व बैठक	15.07.2019 को समय 11:00 बजे-भारतीय मानक समय
निविदा जमा करने की तिथि व समय	03.08.2019 को समय 17:00 बजे-भारतीय मानक समय
निविदा खोलने की तिथि व समय	05.08.2019 को समय 11:30 बजे (भारतीय मानक समय)

विस्तृत निविदा सूचना वेबसाइट www.concorindia.co.in और केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (http://eprocure.gov.in) पर उपलब्ध है। पूर्ण निविदा दस्तावेज निविदा बिक्री अवधि के दौरान वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) पर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

EXECUTIVE DIRECTOR (TECHNICAL)

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	Jet Airways (India) Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	01 April 1992
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs, RoC- Mumbai
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L99999MH1992PLC066213
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Siroya Centre, Sahar Airport Road, Andheri (East), Mumbai – 400099
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	20 June, 2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	16 December, 2019 (180 days)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Ashish Chhawchharia** **Reg. No.** – IBBI/IPA001/IP-P00294/2017-1 8/10538
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Grant Thornton 10C Hungerford Street, Kolkata - 700017 E: ashish.chhawchharia@in.gt.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Please submit claims to: Ashish Chhawchharia** Jet Airways (India) Limited, Siroya Centre, Sahar Airport Road, Andheri (East), Mumbai – 400099 E: rp.jetairways@in.gt.com
11.	Last date for submission of claims	4 July 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a)https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Jet Airways (India) Limited on 20th June, 2019 (copy of the order was communicated to the undersigned on 21 June, 2019).
The creditors of Jet Airways (India) Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 4th July, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. For electronic submission, please access the following link – http://jetairways.wcgt.in, alternatively this link can also be accessed through http://jetairways.com/insolvencyproceedings
The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian Currency at the official exchange rate as on the insolvency commencement date.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

sd/-
Ashish Chhawchharia
Interim Resolution Professional

Date: 24 June, 2019
Place: Mumbai